

राजस्थान में सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई

3543. श्री ओंकार लाल बोहरा : क्या सिंघाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की वर्तमान उत्पादन लागत को देखते हुए राजस्थान में सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) वर्ष 1968-69 में विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जायेगी।

सिंघाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान में बिजली की सप्लाई की लागत में कमी करने के लिये निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:—

(1) एक महत्वपूर्ण भार केन्द्र के निकट राणा प्रताप सागर में अणु शक्ति पर आधारित एक बड़ा ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इसके 1969-70 में चालू होने की संभावना है। इस केन्द्र को उच्च भार अनुपात पर चालू करके और अधिकतम भार भाग को पूरा करने के लिये पन बिजली को उपयोग में लाकर कुल लागत कम की जा सकती है।

(2) राजस्थान ग्रिड को निकटवर्ती पड़ोसी राज्यों के बिजली ग्रिडों से मिलाया जाएगा। इससे भी कुल लागत में कुछ कमी आएगी। खेत्री के रास्ते हरियाणा तथा राजस्थान के बीच 220 के० वी० लाईन का निर्माण किया जा रहा है और इसके 1968 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है। हिसार से जयपुर तक 220 के० वी० लाईन शीघ्रता से बनाई जा रही है। इस लाइन के पूर्ण होने पर राजस्थान को भाखड़ा-नंगल से पन बिजली का पूरा भाग मिल सकेगा जिससे कुल लागत कम हो सकेगी।

(ख) 1968-69 में ग्राम विद्युतीकरण के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता के आबंटन का निर्णय राजस्थान राज्य योजना के लिये कुल केन्द्रीय सहायता के बारे में फैसला होने पर किया जाएगा।

ADIVASIS

3545. SHRI ONKARLAL BOHRA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large number of people of the backward areas are embracing Christian religion on account of their being very poor; and

(b) if so, the schemes drawn up by the Central Government for the economic development of Adivasi areas in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) There has been no official investigation of the factors causing change of religious faith.

(b) The main economic development programmes for the Scheduled Tribes are—Tribal Development Blocks, Forest Labour Co-operatives, Agricultural development, and development of small scale and cottage industries.

पटरी पर पड़े रहने वाले व्यक्तियों को आवास देने की योजना

3546. श्री ओंकार लाल बोहरा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटरी पर पड़े रहने वाले व्यक्तियों के लिये मकान बनाने के लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को कोई अनुदान दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1967-68 के लिये राज्यवार उनका व्यौरा क्या है ?